हिन्दुस्तान

कैबिनेट फैसला: यूपी में 47 साल बाद नया शहर बसाने का निर्णय, झांसी होगा केंद्र

बुंदेलखंड में नोएडा जैसा औद्योगिक शहर बनेगा

35 हजार एकड़ अधिग्रहीत होगी जमीन

63 सौ करोड़ से ज्यादा खर्च अधिग्रहण में

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने जा रही है। झांसी-ग्वालियर मार्ग पर बनने वाली इस औद्योगिक टाउनशिप के लिए 33 राजस्व गांवों की 35 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। इस जमीन के अधिग्रहण में 6312 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही यहां रोजगार की असीमित सुविधाओं का सृजन संभव हो सकेगा। इससे वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था और अब 47 वर्षों बाद नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

छह माह में जमीन का इंतजाम P02

लखनऊ में मंगलवार को कैबिनट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

14 हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित होगा

- इसके माध्यम से कुल 14 हजार हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है।
- यह औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जालौन से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़कर प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ेगा।

क्षेत्रीय विकास के साथ ही रोजगार के अवसर मिलेंगे

- टाउनशिप समेत औद्योगिक स्थापना के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सुविधाओं का यहां समावेश होगा।
- इसके गठन से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।
- जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
- बहुआयामी विकास में तेजी। झांसी के आसपास का क्षेत्र बड़े पैमाने पर विकसित हो जाएगा।

धान का समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ा

70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है

07 प्रतिशत खरीद दर में बढ़ोतरी, खरीद एक अक्तूबर से शुरू होगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने नई धान खरीद नीति तय कर दी है। सरकार ने खरीद मूल्य में 143 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। अब किसानों से बढ़ी हुई दर पर कामन धान 2183 रुपये प्रति कुंतल व ए ग्रेड धान 2203 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023 -24 के तहत खरीद नीति को मंजूरी दे गई। खरीद दर में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खरीद एक अक्तूबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। इसके लिए प्रदेश भर में 4000 क्रय केंद्र खोले गए हैं।

भुगतान 48 घंटे के अंदर हो जाएगा: वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। क्रय एजेंसियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के जरिए धान क्रय के 48 घंटे के अंदर हो जाएगा। धान खरीद वर्ष 2023 -24 के तहत किसानों के हित में धान विक्रय के लिए किसान घोषणा पत्र या हाइब्रिड बीज प्रमाण पत्र में से एक ही प्रपत्र लिए जाने की व्यवस्था की गई है।

छह एजेंसियां खरीदेंगी धान P02

अयोध्या समेत तीन शहरों में ई-बसें चलेंगी

लखनऊ। राज्य सरकार अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। प्रारंभिक दौर में 100-100 बसें चलाने की योजना है। इसके लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। प्रदेश के 17 शहरों में चार चरणों में 4665 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। ब्योरा P02